

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:-125 / 2022

जी.सी.एम.एस नं.-2022 / 269

1. सुखप्रीत कौर पत्नी सतपाल सिंह जाति तरखान उम्र-35 वर्ष निवासी वार्ड नं-24, 24 ए. एस.सी तहसील घडसाना जिला अनूपगढ़ (राज.)
2. जसप्रीत कौर पुत्री सतपाल सिंह उम्र-16 वर्ष
3. पलविन्द्र सिंह पुत्र सतपाल सिंह उम्र-14 वर्ष
4. सिमरनजीत कौर पुत्री सतपाल सिंह उम्र-10 वर्ष—नाबालिगान जरिए कुदरतीवली माता सुखप्रीत कौर पत्नी सतपाला सिंह जाति तरखान उम्र-35 वर्ष निवासी वार्ड नं.-24, 24 ए. एस.सी तहसील घडसाना जिला अनूपगढ़ (राज.)

—वादीगण

बनाम्

1. जंगीर सिंह पुत्र जीवन सिंह जाति तरखान निवासी 3 एस.टी.आर तहसील घडसाना जिला अनूपगढ़ (राज.)
2. सतपाल सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति तरखान निवासी 3 एस.टी.आर तहसील घडसाना जिला अनूपगढ़
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

—प्रतिवादीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित-

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. श्री बलदेव सिंह भगू एडवोकेट    | - वादीगण की ओर से      |
| 2. श्री अनिल कुमार गक्कड़ एडवोकेट | - प्रतिवादीगण की ओर से |



—: निर्णय :-

दिनांक:-28.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण सं.-1 द्वारा चक 2 पी.एम तहसील अनूपगढ़ का मु.न.-9 पं.न.-57/18 का 3.163 हैक्टर भूमि जो प्रतिवादीगण सं.-1 के नाम से दर्ज है को पैतृक सम्पत्ति होना बतलाकर अपने अधिकारो की घोषणा हेतू यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

सुरेश राव आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़



वादीगण ने वाद-पत्र उपरोक्त भूमि जीवनसिंह (प्रतिवादीगण सं.-1 के पिता) ने खरीद की थी जिससे प्रतिवादीगण सं.-1 को विरास्तन में यह भूमि प्राप्त हुई है इसलिए यह भूमि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। वादीगण का 2/3 हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से श्री अनिल कुमार गक्खड़ एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि मन प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पत्ति है यानि इस प्रार्थना-पत्र के साथ बैयनामा दिनांक-19.09.2011 की प्रति संलग्न है जिसके तहत उपरोक्त भूमि स्वयं प्रतिवादीगण सं.-1 द्वारा खरीद की गई है। प्रतिवादी सं.-1 द्वारा उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति में से प्रतिवादी सं.-1 के स्वयं के जिवित रहते हुए वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। विवादित भूमि मुझ प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पत्ति है ना कि पैतृक सम्पत्ति है। इन परिस्थितियों में प्रतिवादी सं.-1 की स्वअर्जित सम्पत्ति में से प्रतिवादी सं.-1 के जीवनकाल में वादीगण कोई हित/हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है, ना ही 2/3 हिस्सा प्रतिवादी सं.-1 ने वादीगण को कभी पारिवारिक समझौता में दिया है, ना ही मौका पर वादीगण का कब्जा है इन परिस्थितियों में वादीगण का वाद विधि वर्जित है। कानून के प्रावधानों के तहत भी प्रतिवादी सं.-1 की स्वअर्जित भूमि में से प्रतिवादी सं.-1 के जीवनकाल में वादीगण कोई हित/हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण विधि वर्जित होने से मौजूदा स्टेज पर खारिज फरमाया वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद में वर्णित वादाधीन सम्पत्ति को सहदायिक सम्पत्ति बताते हुए वाद पेश किया है लेकिन वाद पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे प्रथमदृष्टया उक्त सम्पत्ति सहदायिक सम्पत्ति प्रतीत होती हो वास्तविकता यह है कि उक्त वादाधीन सम्पत्ति प्रार्थी जगीर सिंह की स्वअर्जित, खरीदशुदा, खातेदारी भूमि कृषि है और विवादित भूमि की अप्रार्थीगण सं.-1 रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है। भूमि खरीद के बैयनामा की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादीगण का वाद पूर्णतया: Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग है जो पोषणीय नहीं है तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरुद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं

वादीगण का वाद-पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/वादीगण ने निवेदन किया कि मैं दर्ज भूमि पैतृक सम्पत्ति है चूंकि उक्त तथ्य विधि एवं साक्ष्य का मिश्रित प्रश्न है जो पक्षकारों की साक्ष्य के उपरांत ही तय हो सकेगा। महज प्रकरण को अनावश्यक रूप से देरिना करने के लिए झुठे एवं मिथ्या कथनों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल निरस्ती के है। वादीगण का वाद पत्र किसी भी दृष्टिकोण से विधि द्वारा वर्जित नहीं है। कि प्रतिवादी सं.-1 द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में जो बिन्दू दर्ज किये गये हैं वह विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है जिस सम्बन्ध में दोनों पक्षों की साक्ष्य आने

सुरेश राव  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़



के पश्चात ही तैय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थना-पत्र पोषणीय ना होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अतःजबाब प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन कि प्रतिवादी सं.-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी मय हरजा खर्चा के साथ निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद में वर्णित वादाधीन सम्पत्ति को सहदायिक सम्पत्ति बताते हुए वाद पेश किया है लेकिन वाद पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे प्रथमदृष्टया उक्त सम्पत्ति सहदायिक सम्पत्ति प्रतीत होती हो। उक्त वादाधीन सम्पत्ति प्रार्थी जगीर सिंह की स्वअर्जित, खरीदशुदा, खातेदारी भूमि कृषि है और विवादित भूमि की अप्रार्थी सं.-1 रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है। चूंकि पक्षकारान हिन्दू है, जो हिन्दू विधि से शासित होते है। भूमि खरीद के बैयनामा की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादीगण का वाद पूर्णतया: Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग है जो पोषणीय नहीं है तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरुद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नहीं है। वादीगण का वाद-पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में प्रतिवादी सं.-1 विवादित कृषि भूमि जरिए बैयनामा खरीद कि है जो प्रतिवादी सं.-1 की स्व: अर्जित सम्पत्ति है प्रतिवादी सं.-1 अपने जीवन में विवादित सम्पत्ति का पूर्ण व एक मात्र स्वामी है वादी का हस्तगत वाद पूर्णतया: Frivolous एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होने के कारण एवं वाद के कारण विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण 1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादीगण का वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक-28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सुरेश राव भार ए एस  
उपस्थान्त अधिवक्ता  
अदालत